कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश क्रमांक / एफ-5 / 2023 / 10-11 / 4/5 भोपाल, दिनांक 31 % 23 प्रति,

वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

विषय:— सिंगरौली जिले में बैढ़न—2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ROW भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.0401 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/WATER/151774/2022)

संदर्भ:- मुख्य वनसंरक्षक, रीवा का पत्र क्र/मा०चि०/492 दिनांक 24.01.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मुख्य वनसंरक्षक रीवा ने विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

उपरोक्त प्रस्ताव ROW के तहत भूमिगत पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी नवीन दिशा—निर्देश दिनांक 22.08.2022 के अनुसार ROW में ऑप्टिकल फाइबर केवल लाईन, पानी की पाईप लाईन, विद्युत लाईन तथा गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति के अधिकार नोडल अधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा दिए निर्देशानुसार प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

- 1- उपरोक्त पाईप लाईन की चौड़ाई आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में आवेदन के अनुसार एवं गहराई 02 मीटर से अधिक न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। यह पाईप लाईन सड़क के किनारे—िकनारे ROW में ही डाली जावे।
- 2- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 3- NPV: Net Present Value(NPV) amount of Rs. 38,69,527/- is to be paid for the 4.0401 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 4- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 5- User agency shall restrict the no felling of trees.

- 6- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
- 7- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 8- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 9- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 10- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 11- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 12- Violation of any of these conditions, will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 13- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 14- The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि 38,69,527/- आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से वेबपोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी न की जावे।

(सुनील अग्रवाल) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31/0/23

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 2023 / 10-11 / 4/16 प्रतिलिपि:-

1— मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।

2— महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, म.प्र.। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल